भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 233

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयां

233. श्री नलीन कुमार कटील :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में विनिर्माण इकाइयों के स्थापन हेतु विश्व भर से कंपनियों को आमंत्रित करने के कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व भर की कितनी कंपनियों ने भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है; और

(घ) क्या सरकार ने विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु भारत आने की योजना के बारे में इन कंपनियों के साथ कोई बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख) :** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) विश्व भर में संभावित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कंपनियों तक पहुंच बनाया है जिसमें उन्हें भारत में विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता और भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाओं को शुरू करने या विस्तार करने के लाभों पर प्रकाश डाला गया है। एमईआईटीवाई द्वारा शुरू की गई योजनाएं अर्थात बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस) और संशोधित विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के बारे में विस्तार से बताया गया और इनसे सम्बंधित प्रश्नों का जवाब भी दिए गए। स्पष्ट रूप से संदेश देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं कि भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने का इरादा रखती है और कंपनियों को भारत में विनिर्माण के साथ-साथ बड़े घरेलू बाजार में निर्यात के लिए विनिर्माण पर विचार करना चाहिए।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, भारत में अन्य देशों के दूतावासों और उच्च आयोगों, भारत में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग संघों, भारत में अन्य हिस्सेदारी धारकों, जैसे इन्वेस्ट इंडिया, इंटरनेशनल बैंक (एचएसबीसी, सिटी बैंक), अंतर्राष्ट्रीय कंसलटिंग कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में वैश्विक उनकी आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ सहयोग से आउटरीच गतिविधियाँ की गई हैं। केंद्रित आउटरीच योजना विभिन्न देशों से कंपनियों के साथ की गई है जिसमें अन्य के साथ-साथ दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

(ग) और **(घ) :** दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए रुचि और इच्छा व्यक्त की है। एमईआईटीवाई द्वारा शुरू की गई नई योजनाएं भारत को कंपनियों को आकर्षित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही हैं। राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के साथ भारत में इलेक्ट्रॉनिकी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एमईआईटीवाई इन कंपनियों के साथ खड़ी है। अप्रैल, 2020 से, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कंपनियों के साथ 70 से अधिक बैठकें विभिन्न स्तरों पर अर्थात, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के माननीय मंत्री, सचिव, संयुक्त सचिव और एमईआईटीवाई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, पीएलआई योजना के तहत कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16 आवेदनों को मंजूरी दी गई है - मोबाइल फ़ोन (श्रेणी- 15,000 और इससे अधिक इनवॉइस वैल्यू): 5; मोबाइल फ़ोन (श्रेणी: घरेलू कंपनियाँ): 5; विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों: 6। एसपीईसीएस के तहत 20 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

****